बायें से दायें : दीपक माहुरकर (प्राइसवाटरहाउस कूपर्स इंडिया में ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री प्रैक्टिस के लीडर और डायरेक्टर), आर.एस. शर्मा (पूर्व अध्यक्ष, ओएनजीसी लिमिटेड). सुरेश वेंकट (एडिटर टेक्नोलॉजी एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स, सीएनबीसी टीवी 18), श्याम सरन (चेयरमैन, रिसर्च एंड इंफोर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज), डॉ. राजीव कुमार (महासचिव, फिक्की). डॉ. संजय बारू (डायरेक्टर, जियो-इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज)

भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति

भारत में ऊर्जा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से फोर्ब्स इंडिया ने सीएनबीसी-टीवी-18 और हिन्दुस्तान टाइम्स की मीडिया भागीदारी के साथ एक परिचर्चा का आयोजन किया जिसका विषय था-भागीदारी हासिल करना : भारत के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तेल एवं गैस उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रभावी मॉडल तैयार करना।

Forbes INDIA Presents

The energy Debate

Media partner

फोर्ब्स इंडिया प्रस्तुति ऊर्जा संवाद

जहांगीर अजीज
इंडिया चीफ इकोनॉमिस्ट
जेपी मार्गन

भविष्य में जब हम सार्वजनिक–निजी भागीदारी की स्वीकृति देंगे, हमारे अपने प्राकृतिक संसाधनों की कीमत कैसे आंकी जाएगी। चाहे खनन हो या बिजली, जो भी हो चलेगा लेकिन ऑयल व गैस के मामले में यह बात महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं यह सोचता हूं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेरे विचार में काफी हद तक संशय है क्योंकि यहां काफी स्पष्टता की जरूरत है और काफी बड़ी जरूरत है उस सहमति की कि कौन सा अनुबंध सही है जिस पर सरकार भारत के नागरिकों की ओर से सार्वजनिक निजी क्षेत्र में भागीदारी करेगी।

विगत वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा का विषय एक गम्भीर मुद्दा बन गया है। विश्व बाजार में तेल व गैस की कीमतें तेजी से बदल रही हैं, जिसने भारत को एक नीतिगत ढांचा तैयार करने के लिए विवश कर दिया है, केवल वही सुनिश्चित कर सकता है कि उनके अपने तेल व गैस के भंडारों का उपयोग केवल उन्हीं के नागरिकों के हितार्थ हो। आयातित तेल पर बढ़ती निर्भरता, अनिश्चित विनियामकता और अपारदर्शी प्राकृतिक गैस मूल्यन नीतियों, कुशल कर्मियों की कमी और खराब ढंग से विकसित उत्तरोत्तर अवसंरचना और निकट भविष्य में ऊर्जा के प्रभावी स्त्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधनों पर आश्रितता के कारण देश की नाजुक ऊर्जा सुरक्षा बेहद दबाव में है। पिछले कुछ वर्षों से बढ़ती ऊर्जा मांग के कारण, भारत को किफायती मूल्यों पर ऊर्जा आपूर्तियां हासिल करके अपने ऊर्जा स्त्रोत को बढ़ाना होगा। जबकि देश के पास अधिशेष तेलशोधन क्षमता है और वह पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यातक है, फिर भी प्रमुख निवेश घरेलू अपस्ट्रीम उद्योग में किया जाना है।

प्रभावी विनियामक व्यवस्था के साथ युग्मित बेहद नीति अनुकूल परिवेश निःसंदेह घरेलू ऊर्जा स्त्रोतों के त्वरित विकास का मूल आधार है। ऊर्जा सुरक्षा को सभी हिस्सेदारों द्वारा समेकित कार्यवाही की जरूरत पड़ती है। भारत की ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा हेतु चर्चा, संवाद और सुझाव के तरीकों के लिए फोर्ब्स इंडिया ने सीएनबीसी-टीवी 18 और हिन्दुस्तान टाइम्स की मीडिया भागीदारी के साथ एक परिचर्चा का आयोजन किया जिसका विषय था-भागीदारी हासिल करना : भारत के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए तेल एवं गैस उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रभावी मॉडल तैयार करना। इस संवाद कार्यक्रम में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई जैसे संजय बारू, निदेशक, जियो-इकोनॉमिक्स एण्ड स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, श्याम सरन, चेयरमैन, रिसर्च एण्ड इंफोर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और भूतपूर्व विदेश सचिव, जे.पी. मोर्गन, भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री जहांगीर अजीज, भूतपूर्व तेल एवं प्राकृतिक निगम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर.एस. शर्मा, दीपक माहुरकर-डायरेक्टर एंड लीडर, तेल एवं गैस उद्योग, प्राइस वॉटरहाउस कूपर्स इंडिया और फिक्की महासचिव राजीव कुमार।

आयात पर निर्भरता

परिसंवाद की शुरुआत करते हुए, कुमार ने कहा भारत विश्व स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के मामले में न्यूनतम शोषित देशों में से एक है। 'हमने अपने प्राकृतिक संसाधनों के मात्र 22-25 फीसदी भाग का शोषण किया है। वर्तमान प्रौद्योगिकी क्षमता को देखते हुए तेल अन्वेषण की स्तर बहुत कम है।' उन्होंने 'कहा कि जबकि भारत के पास विश्व का एक चौथाई-विशाल कोयला भंडार है, कोयले की मांग-आपूर्ति का अंतर लगातार बढ़ रहा है साथ ही साथ घरेलू उत्पादन इस मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

यही दशा अन्य प्राकृतिक संसाधनों में भी है। भारत के पास विश्व के कुल प्रमाणिक तेल भंडार का मात्र 0.7 फीसदी है, जबकि गणना के अनुसार वह विश्व के 3.9 फीसदी का उपयोग कर रहा है। इसीलिए उसे अपनी खपत का तकरीबन 75-80 फीसदी हिस्सा आयात करना पड़ता है। उसी प्रकार देश में विश्व के कुल प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार का मात्र 0.8 फीसदी भाग है, जबकि विश्व स्तर पर उसकी खपत 1.9 फीसदी है। फलस्वरूप भारत को एलएनजी के रूप में अपने प्राकृतिक गैस खपत का लगभग 20 फीसदी आयात करना पड़ता है।

श्याम सरन
चेयरमैन, रिसर्च एंड इंफोर्मेशन सिस्टम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज तथा पूर्व विदेश सचिव

यदि आपने ऐसी मूल्य नीति लागू कर दी जो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखती कि इससे पर्याप्त रिटर्न मिलना चाहिए तो बेशक यह उम्मीद कि विदेशी पूंजी आएगी या विदेशी निजी पूंजी का निवेश होगा मेरे विचार से एक सपना ही रह जाएगा।

ज्यादातर नीति कार्यवाहियों में पूरा जोर घरेलू ऊर्जा जरूरतों की सुरक्षा पर दिया गया जबकि आयात के अवसर प्रदान करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और ऐसा समेकित नीति परिवेश तैयार करने पर बल दिया गया ताकि निजी क्षेत्र की तेल और गैस अन्वेषण फर्मों को भारत में प्रवेश करने के लिए समर्थ बनाया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से, निष्क्रिय घरेलू उत्पादन और बढ़ती मांग के कारण देश की निर्भरता आयातित तेलों पर बढ़ी है।

कुमार ने कहा, 'मेरे विचार से, हम समुद्र में व तटों दोनों पर अपने देश में पर्याप्त अन्वेषण डॉलर को आकृष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। हमें ज्यादा प्राथमिकता इस बात पर देनी चाहिए कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन हों।'

रुपये में हाल के अवमूल्यन के कारण भारत के लिए कच्चे तेल का आयात करना महंगा हो गया है जिसके कारण अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव पड़ता है। इसके अलावा तेल के बढ़ते आयात ने भारत के व्यापार घाटे पर भी प्रभाव डाला है। भारत में कच्चा तेल और तेल उत्पादों का आयात 2005-06 में 50.3 बिलियन डॉलर से 2011-12 में तिगुना होकर 140 बिलियन डॉलर हो गया है जो व्यापार संतुलन पर व्यापक प्रभाव डालता है।

पीपीएफ मॉडल एवं एनईएलपी

जहां प्रत्येक क्षेत्र में सरकार की सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणाली सफलतापूर्वक काम नहीं कर रही है वहीं अलग-अलग कारणों की वजह से सरकार निजी तेल एवं गैस उत्सर्जन कम्पनियों को नए ब्लॉकों में लगाने के प्रति सफल नहीं हो पा रही है।

पिछले कुछ समय तक उच्चतर नियामक क्षेत्र होने के कारण सरकार भी इस संदर्भ में पीपीपी सुविधाओं के प्रति कुछ अधिक नहीं कर पाई है। सरन कहते हैं 'हम कोई नियामक या एक प्रोत्साहन व्यवस्था बनाने के योग्य नहीं हो पाए हैं।'

80 और 90 के दशकों में सरकार ने विदेशी निवेश को लुभाने का प्रयास किया था लेकिन विदेशी कम्पनियों के प्रवेश के लिए मूल्य विनियमन एक दुर्गम बाधा के रूप में सामने था। विदेशी निवेश की कमी ने भारतीय तेल एवं गैस भंडारों का उत्सर्जन और उत्पादन में बाधा डाली है। इन कारणों पर ध्यान देते हुए सरकार ने 1997 में तेल एवं गैस क्षेत्र का विनियमन की और पांच वर्ष से अधिक की अवधि में क्रमागत तरीके से प्रशासित मल्य निर्धारण तंत्र की समाप्ति की घोषणा की। ऐसी आशा की गई थी की यह न केवल पेट्रोलियम उत्पादों पर नियंत्रण कम करेगा बल्कि बाजार में विदेशी तेल और उत्सर्जन फर्मों के लिए मार्ग भी प्रशस्त करेगा। बहरहाल, चीजें जिस प्रकार से आशा की गई थी उस तरह से नहीं परिवर्तित हुई। मूल्य नियंत्रण अभी भी क्षेत्र की जरूरतों के विपरीत बना हुआ है। उदाहरण के लिए ओएनजीसी अपने कच्चे तेल उत्पादन हेतु बाजार मूल्य पर निर्भर नहीं रहता है। सरन का कहना था, 'यदि आपने ऐसी मूल्य नीति लागू कर दी जो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखती कि इससे पर्याप्त रिटर्न मिलना चाहिए तो बेशक यह उम्मीद कि विदेशी पूंजी आएगी या विदेशी निजी पूंजी का निवेश होगा मेरे विचार से एक सपना ही रह जाएगा।'

सुरेश वेंकट एवं श्याम सरन

एनईएलपी के साथ इस क्षेत्र को उत्सर्जन करने के लिए अति आवश्यक पूंजी और अति आधुनिक प्रौद्योगिकी लाने का बड़ा कार्यभार दिया गया। ऐसा माना गया कि तेल एवं गैस उत्सर्जन क्षेत्र में एनईएलपी न केवल डॉलर लाएगा बल्कि बड़े नाम भी लाएगा जो इस संदर्भ में रामबाण का काम करेगा। एक दशक से अधिक समय के बाद और एनईएलपी के नौ राउंड्स के बाद अबतक 36 ब्लॉकों में केवल 107 तेल और गैसों की खोज की जा सकी है। इन सबमें केवल 3 ब्लॉकों में 6 खोजों से तेल एवं गैस का व्यावसायिक उत्पादन ही प्रशंसित हुआ है। दुर्भाग्यवश अनिश्चित योजनाओं के साथ एक विषम वित्तीय व्यवस्था का परिणाम है कि अनेक बड़ी वैश्विक तेल एवं उत्सर्जन कम्पनियां ने विभिन्न एनईएलपी राउंड्स में बोली लगाने से स्वयं को दूर रखा।

माहुरकर ने कहा 'कालान्तर में हमने यह महसूस किया है कि कुछ उत्कृष्ट खोजों को छोड़कर, न केवल भूतल जोखिम अभी भी यथावत है बल्कि सतह पर का वातावरण भी ज्यादा नहीं सुधरा है।'

संजय बारू
डायरेक्टर, जियो-इकोनॉमिक्स एंड स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज

भारत में ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती की कठिनाई केवल तभी तक है जब तक हम कीमत के मुद्दे को हल नहीं कर लेते क्योंकि तब तक पूरे निवेश के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। कीमत का निर्धारण ही प्रमुख ऊर्जा सुरक्षा चुनौती है। हमें भारत और बाहर उत्पादन सम्पदाओं की तलाश करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इसे समुचित मूल्य निर्धारण से नहीं जोड़ा गया तथा एक ऐसा निवेश माहौल नहीं तैयार किया गया जिसमें उन अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तो हम यहां से आगे नहीं बढ़ने वाले।

तर्कसंगत मूल्य निर्धारण

मूल्य निर्धारण अपस्ट्रीम सेक्टर का एक सबसे बड़ा अभिशाप हो गया है। उच्च गैस मूल्य सेक्टर की जरूरत बन गया है। जब तक उच्च मूल्य निर्माता को नहीं दिया जाएगा तब तक निजी क्षेत्र के निवेशक निवेश नहीं करेंगे। सभी पैनेलिस्ट सर्वसम्मति से सहमत थे कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा एवं निजी क्षेत्र से प्रतिभागिता को बढ़ाने का समाधान मूल्य निर्धारण मुद्दों पर चर्चा करके ही संभव है। बारू ने कहा कि 'भारत में ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती में कठिनाई यह है कि जब तक हम मूल्य मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे आप निवेश के सभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती की मुख्य बिंदु मूल्य निर्धारण है।'

शरण के अनुसार भी यहां तर्कसंगत मूल्य निर्धारण को लाने से संबंधित मामलों में कदम पीछे हटे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 'हमें भारत और बाहर उत्पादन सम्पदाओं की तलाश करनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। लेकिन यदि इसे समुचित मूल्य निर्धारण से नहीं जोड़ा गया तथा एक ऐसा निवेश माहौल नहीं तैयार किया गया जिसमें उन अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया जिनका हम जिक्र कर रहे हैं तो हम यहां से आगे नहीं बढ़ने वाले।' साइलो में कार्यशील ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित सरकारी विभागों एवं विभिन्न मंत्रालयों के साथ यह व्यापक ऊर्जा क्षेत्र सुरक्षा नीति को बनाने में ज्यादा कठिनाई है।

ऊर्जा सुरक्षा में बाजार बलों की भूमिका को मजबूत करने के लिए कुमार ने कहा कि मूल्य निर्धारण को गैर राजनीतिक करने का समय आ गया है। मूल्य निर्धारण को बाजार बल पर छोड़ने के लिए जोर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रयास यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि मूल्य निर्धारण पर व्यवसायी समूहन एवं एकाधिकार नहीं होना चाहिए।

अनुमोदन की बहुलता एवं नीति की अनिश्चितता

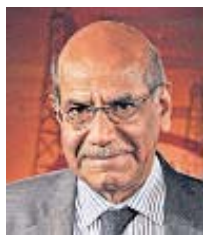

तेल एवं गैस की खोज कार्य हेतु आठ विभिन्न मंत्रालयों से अपेक्षित लगभग 60 विभिन्न अनुमोदन चाहिए जो भारत में प्रचालन आरंभ करने के लिए किसी विदेशी फर्म हेतु बहुत बड़ी चुनौती है। कुमार का कहना था 'आप बेकार नीति को बहुत दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस देश में हम सभी संकटावस्था के समय ही प्रबंधन को मैनेज करने की कला जानते हैं। अगली बार यह संकटावस्था हम लोगों के पास आती है यह इतनी भयावह होगी कि हम लोग इससे वैसे आसानी से बाहर नहीं आ सकते जैसे हम 1991 में बाहर आ गए थे।'

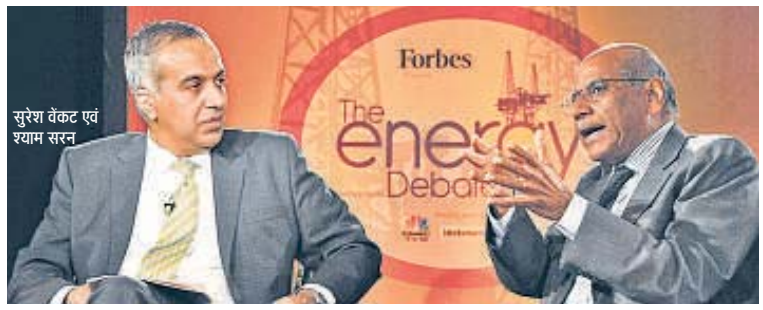

निजी निवेशक तभी आएंगे जब उन्हें अनुकूल वातावरण एवं उचित रिटर्न की गांरटी दी जाए। बहरहाल अगले 8 से 10 वर्षों में किसी भी नीति की अनिश्चितता न हो जब निवेशक की सेंटीमेंट बेहद कम हो ओर निवेशक को जोखिम पूंजी आंवटित की गई हो। यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है कि सरकार जोखिम पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दे।

सहमतिः सभी पैनल के लोग इस बात से सहमत है कि अगर भारत आने वाले समय में ऊर्जा सुरक्षा के किसी भी स्तर को प्राप्त करना चाहता है तो तुरंत ही नीति क्रियान्वियत की जानी चाहिए। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के बदले सरकार चाहती है कि उसका लाभ एवं राजस्व बढ़े।

संदेश बिलकुल साफ एवं सरल हैः सरकार को लाभ कमाने के व्यापार में नहीं आना चाहिए।

Printed and distributed by NewspaperDirect
www.newspaperdirect.com US/Can: 1.877.980.4040 Intern.: 800.6364.6364
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW